Growth of Indian Economy after Independence

Atul Kumar Mishra

Address – Village Po- Muraitha

Thana - Jale,

District - Darbhanga (Bihar)

आजादी के उपरान्त भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास

अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों के अर्थ (धन) और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है। धन का अध्ययन। वैसे अर्थशास्त्र बहुत पुरानी विद्या है। विष्णु पुराण में भारत की प्राचीन तथा प्रधान 18 विद्याओं में अर्थशास्त्र भी परिगणित है। अर्थशास्त्र के सर्वप्रथम आचार्य वृहस्पति थे। उनका अर्थशास्त्र सूत्रों के रूप में उपलब्ध है, किन्तु उसमें अर्थशास्त्र संबंधी सभी बातों का समावेश नहीं है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ही ऐसा ग्रंथ है जो अर्थशास्त्र के विषय पर उपलब्ध क्रमबद्ध ग्रंथ है।

हमलोगो को पता है कि 15 अगस्त सन 1947 को अंग्रेजो के हाथा से आजाद हुए थे। जब कोई भी देश एक दूसरे देश पर आर्थिक शोषण करता है तो उस देश पर आर्थिक स्थिति के विकास में भारी गिरावट आ जाती है। स्वतंत्रता के बाद भारत को एक विखरी अर्थव्यवस्था, व्यापक निरक्षरता और चौंकाने वाली गरीबी का सामना करना पड़ा था।

पुराने समय में सिल्क रूट जो एशिया को यूरोप से जोड़ तथा भारत से होकर निकलता था। जिसमें विदेशी व्यापार में भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी । क्योंकि यदि हम प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो पता चलता है कि भारत में न तो कहीं भी बेरोजगारी थी और न ही गरीबी। प्रत्येक वर्ग अपना स्वयं का व्यवसाय करता था, जिसमें वह पारंपरिक रूप से सिद्धहस्त था । इसलिए भारत सोने की चिड़िया कहलाता था।

आइये हम एक लाईव मिन्ट अखबार में छपा कटिंग से समझने का कोशिश करते है की भारत का विकास एक समय क्या था और उसके बाद कितना गिरावट आयी। **लाईव मिनट के रिसर्च में कैंब्रिज इतिहासकार एंगस मेडीसोन ने अपने रिसर्च में 1700 ई0 में भारत और यूरोप का तुलना विश्व में भागीदारी से किया है। उस वक्त भारत का विश्व के भागीदारी में 22.6 प्रतिशत और यूरोप का 23.3 प्रतिशत था जबकि 1952 में भारत मात्र 3.8 प्रतिशत पे सिमट गया।** भारत की अर्थव्यवस्था में इतनी गिरावट हुआ जबकि कोई भी राष्ट्र आगे की ओर विकास के कदम बढ़ाते है जबकि भारत देश इतने निचे से आजादी के बाद विकास की ओर चलना शुरू किये।

1950 के दशक से कृषि में प्रगति कुछ हद तक स्थिर रही है। 20 वीं शताब्दी की पहली छमाही में इस क्षेत्र की वृद्धि दर लगभग 1 प्रतिशत हुई। आजादी के बाद के युग के दौरान, विकास की दर में प्रति वर्ष 2.6 प्रतिशत की कमी आई थी। भारत में कृषि उत्पादन के लिए, कृषि उत्पादन में वृद्धि और अच्छी उपज वाली फसल की किस्मों की शुरूआत की गई । इस क्षेत्र में आयातित अनजा पर निर्भरता समाप्त करने का प्रबंध किया गया। यहॉ उपज और संरचनात्मक परिवर्तन दोनों के संदर्भ में प्रगति हुई है। देश की सेवा क्षेत्र में प्रमुख विकास, टेली सेवाओं और सूचना प्रौद्योगिकी द्वारा हुआ है। दो दशक पहले शुरू हुई यह प्रवृति सबसे अच्छी है। कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां भारत में अपनी टेली सेवाओं और आईटी सेवाओं को आउटसोर्स करना जारी रखा हैं। सूचना प्रौद्योगिकी के कारण विशेषज्ञता के अधिग्रहण ने हजारों नई नौकरियां दी हैं, जिससे घरेलू खपट में वृद्धि हुई है और स्वाभाविक रूप से, मॉगों को पूरा करने के लिए अधिक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हुआ है।

कोई भी देश में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में यातायात का भी अहम योगदान होता है इसलिए भारतीय परिवहन नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े परिवहन नेटवर्कों में से एक बन गया है, जिसकी सड़को की कुल लंबाई 1951 ई0 में 0.399 मिलियन किलोमीटर थी जो जुलाई 2014 में बढ़कर 4.24 मिलियन किलोमीटर हो गई। इसके अलावा, देश के राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 24,000 किलोमीटर (1947–69) थी, सरकारी प्रयासों से (2014) राज्य राजमार्गो और प्रमुख जिला सड़कों के नेटवर्क का

92851 किलोमीटर विस्तार हो गया है, जिसने प्रत्यक्ष रूप से औद्योगिक विकास में योगदान दिया है।

जैसा कि हमलोगो को पता है बिजली भी अर्थव्यवस्था के विकास में योगदान होता है इसलिये भारत को अपने आर्थक विकास को बढ़ाने के एि बिजली की आवश्यकता है, इसके कारण बहु–आयामी परियोजनाओं को चलाने से उर्जा की उपलब्धता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। आजादी के लगभग सात दशकों के बाद, आज भारत एशिया में बिजली का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। 1947 में 1362 मेगावाट से बिजली की उत्पादन क्षमता 2004 तक बढ़कर 113506 मेगावाट हो गई है।

आर्थिक व्यवस्था में शिक्षा भी उतना ही जरूरत होता है जितना की सब्जी में नमक का क्योंकि शिक्षित व्यक्ति का जितना योगदान आर्थिक विकास में ज्यादा होता है उतना ज्यादा आर्थिक विकास का रफ्तार बढ़ता है क्योंकि वे शिक्षित होकर आधुनिक उपकरण का प्रयोग कर समय की बचत करते हुये आर्थिक व्यवस्था के विकास में योगदान करते है इसलिये आज व्यापक निरक्षरता से खुद को बाहर निकालकर, भारत ने अपनी शिक्षा प्रणाली को वैश्चिक स्तर के समतुल्य लाने में कामयाबी हासिल कर ली है। आजादी के बाद स्कूलों की संख्या में आकस्मिक वृद्धि देखी गई। संसद ने 2002 में संविधान के 86 वें संशोधन को पारित करके 6–14 साल के बच्चों के लिए प्राथमिक शिखा का मौलिक अधिकार बनाया। स्वतंत्रता के बाद भारत की साक्षरता दर 12.02% थी जो 2011 में बढ़कर 74.04% हो गई।

सरकारों द्वारा विभिन्न – विभिन्न प्रकार के योजना स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लाकर एक लंबे संघर्ष के बाद, भारत को अंततः एक पोलियों मुक्त देश घोषित कर दिया गया। कम उम्र के बच्चों में कपोषण, 1979 में 67% से घटकर 2006 में 44% हो गया। सरकार के प्रयासों की वजह से 2009 में तपेदिक मामलों की संख्या घटकर 185 पर पहुँच गई। एच आईवी संक्रमित लोगो के मामलों में भी कमी आयी है। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय (सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 6%) बढ़ने के अलावा, सरकार ने 2020 तक सभी के लिए हेल्थकेयर सहित महत्वाकांक्षी पहलों की शुरूआत की है और सबसे

कम आय वाले समूह के तहत आने वाले लोगों को मुफ्त दवाओं के वितरण का शुभारंभ किया है।

अर्थशास्त्री समजा की रीढ़ हैं। यह समाज के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह समाज के लिए विकास, कल्याण और नीति निर्धारण संबंधी दीर्घ योजनाओं पर विचार विमर्श करते हैं। सरकारी योजनाओं की समीक्षा करने के साथ यह देश के लिए दीर्घ और लघुकालिक महत्व पर मंथन कर देश के विकास पर अपने दायित्यों का निर्वहन करते हैं।